



**सूर्योदय** 06:15 AM    **सूर्यास्त** 06:10 PM  
**अधिकतम** न्यूनतम  
**28 Degree** 16 Degree  
**सोना** 87, 540 Rs.  
**चांदी** 99, 500 Rs.

[www.swatantrabaat.com](http://www.swatantrabaat.com)

हिन्दी वैनिक

# स्पतंश्र बात

R.N.I. No. UPHIN/2010/36179

लखनऊ संस्करण

जन जन की आवाज स्वतंश्र बात

डाक पंजीयन संख्या LW/NP-142/2022-2024

खबरों एवं  
विज्ञापन के लिए  
सम्पर्क करें:-  
मो. ०००७१४७३५३  
7007147353  
Swatantrabaat@gmail.com

वर्ष. 16 अंक. 71

लखनऊ, शनिवार, 15 फरवरी 2025

Swatantrabaat@gmail.com

पृष्ठ. 8 मूल्य 2:00 रुपये

पृष्ठ 4

आसान जिंदगी की चाह ने बेझजती....

पृष्ठ 5

मदिया-बीयर की टुकानों पर जग्धट....

पृष्ठ 8

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा शिक्षा टूर्नामेंट....

## लखनऊ को मिला दो नया प्लाईओवर

588 करोड़ की 114 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण-शिलान्वास

(संवाददाता)

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में विकास की गति को और तेज़ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उपमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दो प्लाईओवर और 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्वास किया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन मिनी स्टेडियम, विकास नार में किया गया। इस दौरान डिटी सोसम ब्रेश पाठक और केशव मीर्ज़ समेत कई

■ खुर्मनगर और  
मुंशीपुलिया प्लाईओवर  
के निर्माण से पहले  
इंजीनियरिंग कॉलेज  
चौरहे से मुंशीपुलिया  
तक का सफर

बड़े नेता भी मौजूद रहे। इन दोनों प्लाईओवर्स के जरिए सीतापुर से आगे जाने वालों को अब रेड लाइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अव्यय रोड से आगे वाले लोगों को भी यह भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो विकास की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है।



संस्थित समाचार

ममता सरकार को  
कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा  
झटका, आएसएस को रैली  
करने की मिली अनुमति

(एंजेसी) कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों को दरकारी करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आएसएस को 16 फरवरी को बद्दलना जिले में रैली करने की संशर्त अनुमति दे दी। कोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा रहा। आएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस रैली को संवाधित करने वाले हैं, उसके आयोजकों ने राज्य पुलिस द्वारा इस आधार पर अनुमति देने से इनकार करने के बाद अदालत का रुख किया था कि चल रही माध्यमिक परीक्षा (पार्श्वमिक परीक्षा) के दौरान लाउडपायर के इस्तमाल से परीक्षायें को परेशानी होती है। बशर्ते आयोजकों को उपस्थित भीड़ की संख्या और लाउडस्पीकर की आवाज पर नियंत्रण रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जरिस्टर्स बीजी नगराला और प्रस्ताव सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेड़कर को जाँच में सहयोग करने के निर्देश दिया है। ममता की आगली सुनवाई 18 मार्च को होती है। खेड़कर की ओर से ये शरणिय वकील सिद्धार्थ लूधा ने कोटी में बचाव की हड्डी सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जरिस्टर्स सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेड़कर को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को अधिग्रहण अर्जी पर जबाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया गया समय भी बढ़ा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

पर रोक बढ़ाई

(एंजेसी) नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व देंगे और आईएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जबकि गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिटी सीएस केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में 114 युनियनी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर तीनों नेताओं ने लोगों को संवाधित किया गया। आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में तेज़ी से बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को जाँच में लेकिन पुस्तिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़वाल की आवाज के बाद लोगों को ज





# सम्पादकीय

## देर से उठाया कदम

भले ही न टाली जा सकने वाली विषम परिस्थितियों के चलते हुआ हो, मणिपुर के विवादित मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफ़ दे दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली की ऐतिहासिक चुनावी जीत का मजा किरकिरा न होने देने के इरादे से उनका इस्तीफ़ दिलवाना बेहतर विकल्प समझा। इस हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा के कारण हुई मौतों और विस्थापन पर सार्वजनिक माफी मांगकर खेद जताने के एक माह से कुछ अधिक समय बाद बीरेन सिंह ने आखिरकार अपना पद छोड़ ही दिया। दरअसल, उनका यह अस्त्र काम नहीं आया। विंडेबना यह है कि उनकी कथित बातचीत का एक आँड़ियो टेप कुछ समय पहले तोक हुआ है। जिसमें टेलीफोन पर हुई वह बातचीत रिकॉर्ड हुई बतायी जाती है, जिसमें जातीय हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका उजागर होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सत्यता प्रमाणित करने के लिये इस टेप को केंद्रीय फेरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिपाफे में यह रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। लगता है कि मणिपुर में विपक्षी दलों द्वारा बीरेन सिंह को हटाने की मुहिम में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के शामिल होने की आशंका का भांपते हुए बीरेन सिंह को इस्तीफ़ देने को कहा गया है। उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर इस्तीफ़ को बचने के एक रास्ते के तौर पर देखा गया है। बहरहाल, राज्य सरकार व पार्टी की छवि को पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है और यह इस्तीफ़ बहुत देर से आया है। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में करीब ढाई सौ लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार स्थिति को संभालने में विफल रही है। विंडेबना यह है कि व्यापक हिंसा व आगजनी के बाद बीरेन को पद से हटाने की मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी सवालों के धेरे में लेता रहा है बहरहाल, अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री बदलने से क्या जपीनी हकीकत में बदलाव आ सकेगा? नया नेतृत्व क्या वह इच्छाशक्ति दिखा पाएगा जिससे मैती व कुकी समुदायों के बीच गहरी हुई ख़ई को पाठा जा सकेगा? निस्संदेह, मणिपुर के लोग न्याय व शार्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का भरोसा जीतना केंद्र सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। ताकि राज्य में शार्ति व सद्व्यवहार कायम हो सके। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र को टालने से राज्य में राष्ट्रपति शासन की आशंका भी जतायी जा रही है। वैसे राज्य में दोनों प्रमुख समुदायों के बीच जिस हृद तक अविश्वास हावी है, उसे देखते हुए शीघ्र सुलह-समझौते की उम्मीद कम ही है। यहां तक कि कुकी समुदाय अपने लिये अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग जोर-शोर से उठाता रहा है, तो वहीं मैती समुदाय इस मांग का प्रबल विरोध करता रहा है। बहरहाल, प्राथमिकता राज्य में शार्ति व्यवस्था स्थापित करने की होनी चाहिए ताकि विस्थापित लोग कनन पर भरोसा

अपने आधार को बरकरार रखा, जैसा कि निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान पैटर्न के विश्लेषण से पता चलता है। यह फैसला मतदान के दिन आप से भाजपा की ओर बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के झुकाव का नीतीजा था, जबकि गरीब कमोवेश आप और कांग्रेस के साथ खड़े थे। तो, सबक यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला। उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर कुछ समझ बना लेनी चाहिए थी, हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता को ध्यान में रखते हुए। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आप और कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वे जमीनी हालत का निष्पक्षता से आकलन करें और भाजपा से मुकाबला करने के लिए अगले दौर की तैयारी करें। अब तक आप दो राज्यों, दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी थीं। अब दिल्ली हार गयी है और सिर्फ पंजाब बचा है। भाजपा अब उत्तर भारत में पंजाब और पूर्वी हिस्से में बिहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी, जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में आप की सरकार थोड़ी अस्थिर रहेगी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के चुनावी पैटर्न में कुछ समानताएं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आप के हाथों पंजाब में परास्त हुई कांग्रेस इस बार पंजाब में आप सरकार को चुनौती देने के लिए खुद को संगठित करने में सबसे अधिक सक्रिय होगी। भाजपा भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी और आप तथा कांग्रेस दोनों को चुनौती देने के लिए नये सहयोगियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। पंजाब के चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहाँ दिल्ली की तरह ही इंडिया ब्लॉक के दो सहयोगी दल एक-दूसरे के आगमे-सामने होंगे। लेकिन एक अंतर यह है कि भाजपा अभी पंजाब में कोई बड़ी ताकत नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी होंगे। इंडिया ब्लॉक के लिए बिहार सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है और साल के अंत में होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व

वाली एनडीई सरकार को चुनावी देने के लिए राजद के नेतृत्व वाले महगठबंधन के साथ एक आदर्श चुनावी समझौता करने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। इंडिया ब्लॉक को किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस को भी सही तरीके से व्यवहार करना होगा क्योंकि पार्टी, अपने कम स्ट्राइक रेट के बावजूद, हमेशा जमीन पर अपनी वास्तविक ताकत की तुलना में अधिक सीटों की मांग करती है। इस बार, राजद और कांग्रेस को बहुत पहले से चुनावी बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जहां एक ओर भाजपा अपनी राजनीतिक और चुनावी रणनीति को लगातार अपडेट करके इंडिया ब्लॉक को हराने के लिए सतर्क और चुस्त है, वहाँ इंडिया ब्लॉक पार्टियों में एक तरह की नींद है। नेतृत्व निष्क्रिय है। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया ब्लॉक नेताओं की कोई पूर्ण बैठक नहीं हुई है। संसद के सत्रों के दौरान केवल समन्वय ही पर्याप्त नहीं है। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और अगले विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, इसलिए यह सही समय है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां मिलें और नवीनतम राजनीतिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा करें और अपनी रणनीति को अपडेट करें। विधानसभा चुनावों और उपचुनावों ने इंडिया ब्लॉक पार्टियों में नये और पुराने दोनों ही चेहरे सामने लाये हैं जो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष की गति को तेज करने के लिए ब्लॉक के लिए बदलाव के बाहक के रूप में काम कर सकते हैं। केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में हुए हालिया उपचुनाव में लोकसभा में प्रवेश करने वाली प्रियंका गांधी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ आगामी लड़ाई में इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी संपर्क हो सकती है। प्रियंका हमेशा सही मुद्दों को आगे बढ़ाती रही है। वह लंबे समय से महिलाओं के मुद्दों, जिसमें नकद हस्तांतरण भी शामिल है, की वकालत करती रही है। वह केंद्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की प्रमुख नेताओं में से एक हो सकती है, क्योंकि भाजपा ने महिलाओं के मुद्दों पर बड़ा ध्यान दिया है और इंडिया ब्लॉक को इसका उचित तरीके से मुकाबला करना होगा। दो अन्य नेता हैं जिन्होंने पिछले दौर के चुनावों और राजनीतिक अभियान में अपनी योग्यता साबित की है। वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीपीआई (एमएल)-लिबेरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। हेमंत ने विधानसभा चुनावों में झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में भाजपा को हराकर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है। यह एक बड़ा काम था क्योंकि भाजपा और आरएसएस ने आदिवासी सीटों पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक हमला किया था। वह देश में आदिवासियों के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे हैं। इसी तरह, दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा उपचुनावों में सीपीआई (एमएल)-एल की बड़ी जीत का आयोजन करके अपनी योग्यता साबित की है। उनके नेतृत्व ने बिहार और झारखंड दोनों में भाजपा की चुनौती का सामना करने में इंडिया ब्लॉक की मदद की है। इस सीपीआई (एमएल)-एल नेता का इस्तेमाल इंडिया ब्लॉक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां बैठक बुलायें और नेतृत्व की नयी लाइन तय करें। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहेंगे और कांग्रेस हमेशा इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री पद के चेहरे का मुद्दा अब बिल्कुल भी प्रासांगिक नहीं है। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में है। जमीनी हालात को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में चर्चा की जा सकती है। अंतर्रिम अवधि में, कई राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने होंगे। इसके लिए इंडिया ब्लॉक के पास एक सुसंगत रणनीति होनी चाहिए। भाजपा के खिलाफ लड़ाई संसद और बाहर सभी मोर्चों पर लड़ी जानी चाहिए। राहुल संसद के अंदर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकते हैं, जबकि ममता-स्टालिन की जोड़ी को 2025 और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के संचालन में गतिशीलता लाने का काम सौंपा जाना चाहिए।

# दिल्ली में आप की हार से इंडिया ब्लॉक को सबक लेते हुए आगे देखना होगा

नित्य चक्रवर्ती

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आप आदर्म पार्टी (आप) की हार और भाजपा की जीत निश्चित रूप से विपक्षी ईंडिया ब्लॉक के लिए झटका है, लेकिन इसका मतलब आप का अंत या ईंडिया ब्लॉक के लिए अंतिम झटका नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय मण्डिया और टीवी चौनलों के कुछ टिप्पणीकार इसे पेश कर रहे हैं जिन लोगों ने दिल्ली के मतदाताओं के मूड का अध्ययन किया है, वे पहले से ही जानते थे कि 2025 के चुनाव में, भाजपा को हराकर सत्ता बरकरार रखना आप वे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के दो कार्यकाल पूरे होने के बाद सत्ता विरोधी लहर थी। अंतिम निर्णायक बात यह रही कि मतदान से चार दिन पहले 1 प्रवरी को घोषित 2025-26 के केंद्रीय बजेय में आयकर में बड़ी छूट दी गयी और केंद्र सरकार वे कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गयी। भाजपा के पक्ष में जनादेश दिल्ली वेतनभोगी मध्यम वर्ग द्वारा लाया गया, जो दिल्ली वेतनभोगी मध्यम वर्ग में से अधिकांश हैं। उन्हें सीधे नकद लाभ मिला। निश्चित रूप से इसका कुछ दिनों बाद मतदान के दिन तक्ताल प्रभाव पड़ा। पिछे भी, मतदान वे आंकड़े बताते हैं कि लडाई एकतरफ नहीं थी। बल्कि यह एक कड़ा संघर्ष था। भाजपा को 45.56 प्रतिशत वोट मिले, जबकि आप को 43.57 प्रतिशत, यानी केवल 2 प्रतिशत का अंतर, हालांकि सीटों के मामले में भाजपा को 48 और आप को केवल 22 वोट मिले। इसके अलावा, ईंडिया ब्लॉक की दोनों पार्टियों आप और कांग्रेस के वोटों को मिलाकर आप-कांग्रेस को लगभग 50 प्रतिशत वोट मिले और सीटों के मामले में, अगर गठबंधन होता तो ईंडिया ब्लॉक के खाते में 14 और सीटें आतीं। इसका मतलब है कि अगर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता तो ईंडिया ब्लॉक कुल 70 सीटों में से 36 सीटें जीतकर मामूली जीत हासिल कर सकता था। इसके अलावा, आप ने दलितों, गरीबों और मुसलमानों वे

# क्या काग्रेस का गठबन्धन से निफलने का वक़आ चला है?

ડૉ. દાપક પાચપાર

इस बात से सभी की सैद्धांतिक सहमति है और समझदारी भी इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को समिलित मुकाबला करना होगा। 2014-19 एवं 2019-24 के लिये हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की सफलता का राज यही था कि वह अपने विरोधियों के मतों को बांटने में सफल रही थी। इस बात को तमाम राजनीतिक दल भाँपु चुके थेय अब भी समझ रहे हैं कि आपस में लड़कर वे भाजपा का ही पफयदा कर रहे हैं परन्तु इस विशालकाय देश में बेशुमार राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके अस्तित्व के अपने अपने प्रयोजन हैं और जो विभिन्न राज्यों या समूहों की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करते हैं। भाजपा के अलावा कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसकी राष्ट्रीय पहचान और देशव्यापी उपस्थिति है। इनके लिये अलग चुनाव लड़ना खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिये अनिवार्य सा होता है। इसके बावजूद विपक्ष एक होने का जो नाम नहीं ले रहा था उसके पीछे अनेक कारण थे। पहला था स्थानीय पहचान खोने का डर और दूसरे, किसी अन्य दल का नेतृत्व स्वीकारने में रजामंद न होना। पिछले करीब डेढ़ वर्षों से कांग्रेस के नेतृत्व में बना ईंडिया गठबन्धन कतिपय सफलताओं और कुछ नाकामियों के साथ फिर ऐसी जगह पर खड़ा है जहां कांग्रेस को इस बात की नाप-ताल करने कि क्या उसे आवश्यकता है कि वह गठबन्धन का नेतृत्व करता रहे, उसके साथ रहे अथवा अकेले चुनावों में उतरे? उसके सहयोगी गठबन्धन जिस हिसाब से उसे अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके चलते कोई आश्र्वय नहीं होना चाहिये कि तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेता सवाल करें कि कांग्रेस को सोचना होगा कि वह अकेले चले या गठबन्धन में बढ़ी रहे। ईंडिया के गठन को देखें तो वह कांग्रेस की ही देन है।

2023 को जब धूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकल कर 30 जनवरी, 2024 को कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक (श्वारात जोड़े यात्रा) राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया था, तभी से इसकी अवधारणा ने जम्म लिया था। राहुल की दूसरी यात्रा 14 जनवरी, 2024 से मणिपुर से निकली तथा मुम्बई में 18 मार्च को मुम्बई में समाप्त हुई थी। इस हाईड्रीड यात्रा को श्वारात जोड़े चाय यात्राश कहा गया। इसके समाप्त पर मुम्बई में जब वृहद आम सभा हुई थी तो बीसियों गैर भाजपायी दल उसमें शामिल हुए थे और एक तरह से मुकम्मल गठबन्धन बन गया था। ईंडिया के नाम से बना यह प्रतिपक्षी गठजोड़ भारत की विविधता को तो दर्शाता ही है, वह प्रतिरोध के देशव्यापी विस्तार का भी प्रतिबिम्ब था। पहली बार लगा कि भाजपा को टकरादी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री व नीतीश कुमार जनता दल प्रमुख नीतीश कुमार व राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जैसे लोगों ने गठबन्धन को महत्वपूर्ण मौकों पर धोखा दे दिया, पिर भी कई दलों ने गठबन्धन का मजबूती से साथ दिया। मामूली मतभेदों के बाद भी वे संग-संग चले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (राष्ट्रीय जनता दल), तमिलनाडु के सीएम (द्राविड़ मुनेत्र कषगम) एमके स्टालिन, झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमत सरेन (झारखण्ड मुक्ति मोर्चा), महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना (यूबीटी गुट) उद्घव ठाकरे व नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के चीफशरद पवार, जमू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला (नेशनल कांग्रेस) जैसे भी शामिल हैं जो उत्तर-चंद्रावों में भी गठबन्धन का हिस्सा बने हुए हैं। जम्म-कश्मीर की महबूबा मफ्ती (पीपल्स डेमोक्रेटिक

अर्विंद केजरीवाल (आम आदमी पार्टी-दिल्ली व पंजाब) गठबन्धन के साथ तो हैं पर अपने-अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं। तालमेल का अलग-अलग पैटर्न ही इसकी कमजोरी है। इसके चलते उसके उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता जो इसके गठन के दर्मियान सोचे गये थे। ऐसे में जब कटिहार के सांसद तारिक अनवर उपरोक्त सवाल करते हैं तो सम्भवतर निराशा के चलते उहोंने वह मुश्व उठाया होगा कि आधे-अधूरे गठबन्धन से बेहतर है कि अकेले लड़ा जाये। अनवर के सवाल पर गम्भीरता से सोचे जाने की जरूरत है क्योंकि यह प्रश्न और भी कांग्रेसियों के मन में हो सकता है। गठबन्धन एवं चुनावों के दौरान सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के साथ होने वाला धालमेल सभी को दुविधा में डालता है। अकेले लड़ने में कम से कम वह असर्मज्जस की स्थिति तो नहीं ही रहेगी। हालांकि कांग्रेस को देश का नक्शा सामने रखकर सीटवार इस बात का आकलन करना चाहिये कि अकेले लड़ने की बजाये मिलकर लड़ने पर उसका कितना लाभ या नुकसान हो रहा है। यदि कुछ ही सीटों की कीमत पर कांग्रेस गठबन्धन धर्म निभाने के फेर में अपना ज्यादा नुकसान कर रही है तो उसे पुनर्विचार करने की जरूरत है। सवाल हो सकता है कि यदि परिस्थितियां गठबन्धन की मांग करती हैं तो उसका नेतृत्व करने वाले दल का अकेले लड़ने हेतु बाहर हो जाना कितना समयानुकूल व वाजिब होगा। हालांकि विपक्षी एकजुटता तो हर स्थिति व काल में वांछनीय और स्वागत योग्य ही रहेगी लेकिन क्या जरूरी है कि बिगड़े सहयोगियों को हैंडल करने में कांग्रेस अपना वक्त व ऊर्जा जाया करे? ममता बैनर्जी अवर फेरेट राहुल जी कहते-कहते पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती को तीन सीटों पर सिमट पर मंजर है लेकिन मिलकर जेल जाने का खतरा मौल ले सकते हैं, परन्तु जब देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाकर सचिव पोस्टर दिल्ली के चौक-चौराहों पर टांगने की बारी आती है तो वे राहुल को तीसरा सबसे अधिक भ्रष्टाचारी निरुपित करने में देर नहीं लगता। ऐसे में कांग्रेस को ऐसे गठबन्धन और उसके सहयोगियों को लम्बे समय तक ढोना अनावश्यक प्रतीत होना स्वाभाविक है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हारने के बाद जो तंज किया कि अकेले लड़े और हारते रहो, वस्तुतरु एक गम्भीर टिप्पणी है। अब राज्यसभा सदस्य कपिल सिङ्गल भी कहते हैं कि कांग्रेस व गठबन्धन को अभी से तय करना होगा कि 2029 का चुनाव कैसे लड़ना है। एकजुटता के पक्षधर जानते हैं कि मौजूदा हालात में एकता होनी चाहिये, पर वह दिखनी भी तो चाहिये और उसके नतीजे भी मिलने चाहिये। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस मिलकर लड़ना चाहती थी पर आप ने उसका दोस्ती का हाथ झटक दिया जो उसे तो भारी पड़ा ही, गठबन्धन में बड़ी दरर छोड़ गया। हालांकि राहुल व कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एकता को बनाये रखने की इसलिये कोशिश करेंगे क्योंकि वे इस लड़ाई में सीधे उतरे हुए हैं। वे भाजपा की शक्ति को जानते हैं। कांग्रेस के बहुत से नेता खुद को भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधी लड़ाई से बचाकर चलते हैं। उनके सामने खुद का कैरियर है या वे अपने किसी की सेटिंग की मिलकर में रहते हैं अथवा केन्द्रीय जांच एजेंसियों से बचाये रखना चाहते हैं। अकेले लड़ना निश्चित ही दुर्लभ है पर अब वक्त आ गया है कि पार्टी इसका हन अध्ययन करे कि अकेले लड़ने में उसका हासिल क्या होगा और अभी वह क्या गंवा रही है। लम्बी लड़ाई व बड़ा जोखिम उसके खाते में होगा पर कांग्रेस सक्षम है।

# आसान जिंदगी की चाह ने ब्रेक्जिट से डिपोर्ट होने पर किया मजबूर

बहुत ब-आवरू हा कर तिर कूच स हम  
निकले...गालिब के इस शेर से उन डिपोर्ट किए गए  
भारतीयों का दर्द समझा जा सकता है, जिन्हें अमेरिका से  
भारत वापस भेजा गया है। अमेरिका से निर्वासित किए  
गए 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिका  
सैन्य विमान सी-17 ग्लोबमास्टर से वापस भारत भेजा  
गया है। इनमें 104 भारतीय शामिल हैं। जिसमें 72 पुरुष  
19 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। अमेरिका में करीब 18  
हजार प्रवासी भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। इन्हें भी  
वापस भारत भेजा जाएगा। डंकी मार कर अमेरिका तब

A Boeing 747 aircraft is shown from a side-on perspective, parked on the tarmac. The aircraft has a white fuselage with grey stripes and a green tail fin featuring a globe logo. It is positioned behind a chain-link fence, with a city skyline visible in the background under a clear sky.

है। आकषण का यहां जाल मुसाबत का सादा साबात होता है। जब वैध तरीके से अमरीका में प्रवेश नहीं मिलता तो डंकी रास्ते से युवाने की कोशिश की जाती है। बेरोजगारी की समस्या और खुब धन कमाकर अच्छी जिंदगी जीने की चाह कई भारतीय युवाओं को विदेश जाकर रोजगार तलाशने के लिए प्रेरित करती है। आंकड़े बताते हैं कि डंकी रूट से भारत से अमेरिका जाने वालों की संख्या काफी है। विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाने का सपना देखने वाले हजारों लोग हर साल डंकी रूट से अमेरिका जाने का जोखिम उठाते हैं। डंकी रूट एक ऐसा जोखिम है जिसमें हर कदम पर परेशानी ही परेशानी है और कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सीमा पार करने के लिए लोगों को कई महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मानव तस्कर इस रूट में संचालक की भूमिका में होते हैं, जो अवैध रूप से देशों की सीमाएं लांघने में मदद के बदले लोगों से अच्छी खासी रकम लेते हैं। कई बार यह रकम 50 से 85 लाख रुपये तक होती है। अमेरिका में डॉलर में धन कमाकर भारत पैसा भेजने वाले लोगों के घर अलग से पहचाने जाते हैं। कई परिवारों के लिए उनके किसी सदस्य का अमेरिका में होना स्टेटस माना जाता है। वहीं, भारत में 2018 से लगातार बेरोजगारी दर गिरने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या युवाओं के पलायन का कारण मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर भारत के पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोग बेहतर बेतन वाली नौकरियों की तलाश में अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया या निष्कासित किया गया था, जबकि 2021 में यह संख्या 30,662 थी। डंकी रूट का मतलब ऐसे रास्ते हैं जो अवैध रूप से लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए यह एक लंबी और चक्रवर्दार यात्रा होती है। पंजाब में डंकी रूट एक दशक से भी ज्यादा समय से एक खुला रहस्य रहा है। यह शब्द पंजाबी शब्द ढुंकी से आया है, जिसका अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह कदम। दिसंबर 2023 में डंकी प्रेक्टिस तब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आई थी जब प्रांत से मानव तस्करी के संदेह में दुर्बुद्ध से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर विमान को रोक दिया था। इनमें से अधिकांश को वापस भारत भेज दिया गया था। अमेरिका और युरोपीय देशों की चकाचौंध भरी जिन्दगी की जीने की चाह में हर साल सैकड़ों लोग कालकलवित हो जाते हैं। शरणार्थियों और प्रवासियों को अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते समय समुद्र और जमीन पर चरम प्रकार की हिंसा, शोषण और मौत का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर), अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) और मिशन्श्रित प्रवासन केंद्र (एमएमसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 के पहले पांच महीनों में कैनरी द्वीप समूह के लिए अटलांटिक मार्ग पर 5,000 लोग मारे गए। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 700 प्रतिशत की वृद्धि है। अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर से ज्यादा लोग पार करते हैं और रेगिस्तान में शरणार्थियों और प्रवासियों की मौतें समुद्र में होने वाली मौतों से दोगुनी होने का अनुमान है। मध्य भूमध्यसागरीय प्रवास मार्ग दुनिया में सबसे खतरनाक मार्गों में से एक बना हुआ है। लोग बहुत खतरनाक यात्राओं पर जाने का जोखिम उठाते हैं। प्रवास मार्ग पर अपनाने के लिए मजबूर होने वाले प्रमुख कारकों में मूल देशों और मेजबान देशों में बिगड़ती स्थिति शामिल है। जैसे कि साहेल और सूडान में नए संघर्ष- पूर्व और अफ्रीका के हाँने में नई और दीर्घकालिक आपात स्थितियों पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव, साथ ही शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति नस्लवाद और जेनोफोबिया।

उन्होंने जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए उपर मिलर के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। इन आदेशों में थे- जन्मसिद्ध नागरिकता को ख्रम करना और दक्षिण सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करना। नीतिगत मामलों के डिप्टी डायरेक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वरूप में मिलर ने ट्रॅप के आप्रवासन एंजेंडे को लागू करने के लिए कई कार्यकारी आदेशों का मसांदा तैयार करकी अगुवाई की। इसमें अवैध प्रवासियों के आने पर रोक और अमेरिकी धरती पर पहले से मौजूद रहने वालों को प्रत्यर्पित करने का बादा किया गया है। इन आदेशों में से एक है जन्म आधारित नागरिकता व ख्रम करना। यह एक ऐसा क़दम है जो अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन में गारंटी दिए गए ऐतिहासिक अधिकारों को नकारता है और इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्ट्रीफ्म मिलर ट्रॅपिज्म की सबसे कठूल नीतियों के वास्तुकार ही नहीं हैं, बल्कि एक रणनीतिकार भी हैं जिन्होंने इन्हें असरदार तरीके से लागू करने के दावपें में महारत हासिल कर ली है। ऐसा बहुत कम होता कि अमेरिका में रह रहे अवैध आप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के काम में सेना को लगाया जाए, लेकिन ट्रॅप के द्वारा कार्यकाल में प्रवासियों को भेजने के मिशन में सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका में बसना एक ऐसा सपना है जिसे ज्यादात लोग हकीकत में बदलना चाहते हैं, खासतौर पर अमेरिका जीवन शैली और सुविधाएं सभी को आकर्षित करती हैं।

मजबूत होती है इसलिए जन्मदिन, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत व म

पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और दो घंटे मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान रखें। साथ ही पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करें। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और चंद्रमा शुभ फल देता है।

इससे दिमाग को पूर्ण शक्ति मिलती है और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अगर इस समय पर नाश्ता करेंगे तो दिमाग भी कमज़ोर होता है।

7-इस उपाय से चंद्रमा की स्थिति होती है मजबूत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में चंदमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चावल की खीर बनाएं और उसको गरीब व जरुरतमंदों को दान कराएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोमवार के दिन दूध न पीएं। साथ ही हर रोज आंगवाला और दो अखरोट जरुर खाएं। इसके बाद सोने से पहले नाक में बादाम के तेल की बूँदें डालें। ऐसा करने से मानसिक रोग दूर होता है और चंदमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

पर मिलर के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। इन आदेशों में थे—जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करना और दक्षिण सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करना। नीतिगत मामलों के डिप्टी डायरेक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा रूप में मिलर ने ट्रॉप के अप्रवासिन एंजेंडे को लागू करने के लिए कई कार्यकारी आदेशों का मसौदा तैयार करने की अगुवाई की। इसमें अवैध प्रवासियों के आने पर रोक और अमेरिकी धरती पर पहले से मौजूद रहने वालों को प्रत्यर्पित करने का वादा किया गया है। इन आदेशों में से एक है जन्म आधारित नागरिकता वालों को खत्म करना। यह एक ऐसा कदम है जो अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन में गारंटी दिए गए ऐतिहासिक अधिकार को नकाराता है और इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्टीफन मिलर ट्रॉपिजम की सबसे कठूनी नीतिकारी को वास्तुकार ही नहीं हैं, बल्कि एक रणनीतिकार भी हैं जिन्होंने इन्हें असरदार तरीके से लागू करने के दावपें में महारत हासिल कर ली है। ऐसा बहुत कम होता कि अमेरिका में रह रहे अवैध आप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के काम में सेना को लगाया जाए। लेकिन ट्रॉप के दूसरे कार्यकाल में प्रवासियों को भेजने के मिशन में सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका में बसना एक ऐसा सपना है जिसे ज्यादा लोग हकीकत में बदलना चाहते हैं, खासतौर पर अमेरिका की जीवन शैली और सुविधाएं सभी को आकर्षित करती हैं।

जोखिम है जिसमें हर कदम पर परेशानी ही परेशानी है और कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सीमा पार करने के लिए लोगों को कई महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मानव तस्कर इस रूट में संचालक की भूमिका में होते हैं, जो अवैध रूप से देशों की सीमाएं लांघने में मदद के बदले लोगों से अच्छी खासी रकम लेते हैं। कई बार यह रकम 50 से 85 लाख रुपये तक होती है। अमेरिका में डॉलर में धन कमाकर भारत पैसा भेजने वाले लोगों के घर अलग से पहचाने जाते हैं। कई परिवर्तनों के लिए उनके किसी सदस्य का अमेरिका में होना स्ट्रेटस माना जाता है। वहाँ, भारत में 2018 से लगातार बेरोजगारी दर गिरने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या युवाओं के पलायन का कारण मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर भारत के पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोग बेहतर बेतन वाली नौकरियों की तलाश में अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया या नियकासित किया गया था, जबकि 2021 में यह संख्या 30,662 थी। डंकी रूट का मतलब ऐसे रस्ते हैं जो अवैध रूप से लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए यह एक लंबी और चक्रवादी यात्रा होती है। पंजाब में डंकी रूट एक दशक से भी और प्रवासियों को अप्रीका महाद्वीप से गुजरते समय समुद्र और जमीन पर चरम प्रकार की हिंसा, शोषण और मौत का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर), अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) और मिशन्श्रित प्रवासन केंद्र (एमएमसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 के पहले पांच महीनों में कैनरी द्वीप समूह के लिए अटलांटिक मार्ग पर 5,000 लोग मारे गए। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 700 प्रतिशत की वृद्धि है। अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर से ज्यादा लोग पार करते हैं और रेगिस्तान में शरणार्थियों और प्रवासियों की मौतें समुद्र में होने वाली मौतें से दोगुनी होने का अनुमान है। मध्य भूमध्यसागरीय प्रवास मार्ग दुनिया में सबसे खतरनाक मार्गों में से एक बना हुआ है। लोग बहुत खतरनाक यात्राओं पर जाने का जोखिम उठाते हैं। प्रवास मार्ग पर अपनाने के लिए मजबूर होने वाले प्रमुख करारों में मूल देशों और मेजबान देशों में बिगड़ती स्थिति शामिल है। जैसे कि साहेल और सूडान में नए संघर्ष- पूर्व और अप्रीका के हर्नै में नई और दीर्घकालिक आपात स्थितियों पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव, साथ ही शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति नस्लवाद और जेनोफोबिया।







